Greater vigilance on banks and insurance companies

430. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Central Vigilance Commission has called for much greater vigilance in public sector organisations such as banks and insurance companies in view of the larger economic and commercial role played by them;

(b) if so, what is the reaction of Government on the views of the Central Vigilance Commission;

(c) whether Government propose to conduct vigilance against bank managers and agents of insurance companies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Central Vigilance Commission (CVC) on a continuing basis reviews the vigilance activities in public sector banks/financial institutions and insurance companies and given suggestions/advice from time to time. The vigilance activities of these institutions are monitored and reviewed in the respective organisations, CVC and Government.

(c) and (d) In addition to Central Bureau of Investigation, internal vigilance machinery exists in all public sector banks/financial institutions|insurance companies for maintenance of vigilance. With regard to vigilance matters pertaining to officers of and above scale III in public sector banks, action is taken in consultation with CVC. The Government also have annual action plan on anti-corruption measures which is monitored on quarterly basis. There is no proposal to bring agents of insurance companies under the vigilance cover. However, in case agents indulge in corrupt practices, action can be taken according to the provisions of Insurance Act, 1938.

PHD Chamber of Commerce's Recommendation on LIC

431. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the PHD Chamber of Commerce and Industry has recommended splitting up of the Life Insurance Corporation into a number of units and the creation of offshore financial centres to integrate India's financial operations with the World's financial markets; and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) It is not considered administratively desirable to split Life Insurance Corporation into a number of units.

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनियमितताएं

432. श्री राम सिंह राठवा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऋण देने और ऋण माफ करने में अनियमितताएं बरतने के संबध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की कोई जांच करायी है ; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा सहित देश के विभिन्न भागों से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी, संवितरण और माफी और कथित अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ उठाया जाता है। जहां तक अशोध्य ऋणों और घाटों को बट्टे खाते डालने और समझौता प्रस्तावों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे ऐसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए अपने विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करें। बैंकों की जांच के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक की नजर में बैंकों में ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों से संबंधित व्याप्त विभिन्न कमियां भी आई हैं। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकों द्वारा अपने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक

433 **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की नई शाखाएं खोलने का विचार रखती हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन शाखाओं को खोले जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या नीचे दी गयी :—

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या		
	बडोदरा	सूरत	अहमदाबाद
भारतीय स्टेट बैंक . . .	32	9	14
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र . . .	—	—	1
बैंक आफ बड़ौदा	50	51	5
बैंक आफ इंडिया . . .	8	6	8
बैंक आफ महाराष्ट्र . . .	2	2	1
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया . . .	12	6	3
देना बैंक	10	21	23
इण्डियन बैंक . . .	1	1	—
इंडियन ओवरसीज बैंक . . .	6	1	5
सिंडिकेट बैंक	—	5	—
यूको बैंक	1	1	2
यूनियन बैंक आफ इंडिया . . .	8	4	4
विजया बैंक	1	—	—
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स . . .	—	—	1